for revamping the Public Distribution System specially in areas like farflung hills;

(b) if so, the number of new shops opened in the hilly region of Darjeeling District in West Bengal during the last two years; and

(c) the number of persons brought under this system from that area till the date?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) The Central Government in consultation with the State Government and U.T. Administrations identified over 1700 Blocks covered under various area specific programmes like Drought Prone Area Programme (DPAP), Desert Development Programme (DDP), Designated Hill Areas (DHA) and Integrated Tribal Development Projects (ITDP). The State Governments were requested to open additional fair price shops in areas under served or unserved. As per reports received from State Governments and UT Administrations till 15.8.93, more than 10600 fair price shops have been opened under the Revamped Public Distribution System (RPDS). The Government of West Bengal have reported to have opened 39 additional fair price shops in the State under RPDS.

(b) and (c) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को सामान की सप्लाई

3526. **श्री दिलीप सिंह जदेव** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के अगम्य आदिवासी क्षेत्रों में वर्ष 1990-91 और 1991-92 में राशन प्रणाली के अंतर्गत अग्रिम भंडारण हेतु आवंटित खाद्यान्नों, खाद्य तेलों और मिट्टी के तेल की कुल मात्रा कितनी थी और उसका मूल्य कितना था;

(ख) राज्य सरकार ने प्रश्नांकित सामग्रियों की वास्तव में कुल कितनी मात्रा प्राप्त की और उन अगम्य क्षेत्रों में कितनी मात्रा का भंडारण किया गया;

(ग) ऐसे क्षेत्रों में वर्षाकाल में इन भंडारित सामग्रियों की कितनी मात्रा का वितरण किया गया और इन सामग्रियों की कितनी मात्रा खराब होकर बेकार चली गई तथा वर्षाकाल के बाद कितनी सामग्रियों का वितरण किया गया ; और

(घ) इन अवितरित, खराब एवं नष्ट हो गई सामग्रियों के मूल्य और इन्हें इन अगम्य क्षेत्रों तक ले जाने पर आये परिवहन व्यय का ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कामालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति

3537. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में गुजरात में आवश्यक वस्तुओं का कोटा न लेने और उसका राशन कार्डधारियों में वितरण न करने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली बहुत सी उचित दर दुकानों को रद्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;